

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

हलधर



किसान

वर्ष 01 अंक 03

मई 2022

पृष्ठ-8 मूल्य -5.00 रुपये

कर्ज माफी से नहीं सुधरते किसानों के हालात, इससे होती है और अधिक कर्जदार होने की संभावना

ऐसी घोषणाओं से किसानों में जानबूझकर कर्ज ना लौटाने की प्रवृत्ति की संभावना को मिलता है बढ़ावा : नाबार्ड

हलधर किसान। देश की राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने कर्जमाफी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। नाबार्ड ने नाबार्ड ने गहन अध्ययन के बाद जारी कि एक रिपोर्ट में किसानों की कर्जमाफी संबंधी घोषणाओं की परंपराओं को पूरी तरह खारिज किया है। रिपोर्ट में कहा है कि कर्जमाफी संबंधी घोषणाओं से किसानों के हालात बिल्कुल नहीं सुधरते हैं, बल्कि इससे किसानों के ज्यादा कर्जदार होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है।

नाबार्ड ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि ऐसी घोषणाओं से किसानों में जानबूझकर कर्ज ना लौटाने की प्रवृत्ति की संभावना अधिक बढ़ती है और ईमानदार किसानों भी आदतन कर्ज ना लौटाने वाले किसानों की सूची में शामिल हो सकते हैं। इस कारण कर्ज माफी का यह चक्र लगातार चलता रहता है। नाबार्ड ने कर्ज माफी को लेकर किसानों का व्यवहार को अच्छे से समझने के लिए महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कुल 3000 किसानों से रूबरू हो कर इस मुद्दे पर बात की थी। जिसके बाद ही नाबार्ड ने अपनी यह रिपोर्ट पेश की है।

पंजाब प्रांत का एक किसान प्रत्येक साल औसतन 3.4 लाख रुपये का कर्ज लेता है

नाबार्ड ने किसानों से कर्जमाफी पर बातचीत के बाद पाया है कि अधिकांश किसान संस्थागत स्रोतों से ज्यादा कर्ज लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार किसानों



को बैंक या अन्य संस्थाओं से अधिक से अधिक 7.7 फीसदी ब्याज पर कर्ज मिलता है, वही दूसरी गैर संस्थागत स्रोतों से कर्ज लेने पर किसानों को 9 से

21 फीसदी तक की दर से ब्याज चुकाना पड़ता है। ऐसे में किसान संस्थागत स्रोतों से अधिक कर्ज लेने की कोशिश करते हैं। साथ ही रिपोर्ट में बताया गया

किसानों पर बढ़े कर्ज के ये भी हैं कारण

उल्लेखनीय है कि पंजाब, महाराष्ट्र, मप्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों द्वारा की गई कर्जमाफी भी किसानों पर कर्ज का दबाव कम नहीं कर पाई है। कर्जमाफी की नीति में गलतियों के अलावा किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई कदम न उठाने के कारण किसान फिर कर्ज की उसी दलदल में फंसे हैं, जिसमें पांच साल पहले थे। यह दावा रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में तीनों राज्यों में किसानों पर चढ़े कर्ज के कारणों को भी उभारा गया है। खेती की बढ़ी हुई लागत, फसल व पशुधन को नुकसान और किसानों की आय में आई अस्थिरता किसानों पर कर्ज के प्राथमिक कारण हैं। वहीं मार्केटिंग की समस्या भी कर्ज बढ़ने का कारण रही। इसके अलावा बाजारी लेनदेन में गैर पारदर्शिता और बिचौलियों पर अत्यधिक निर्भरता ने भी किसानों के संकट को बढ़ाया। बढ़ती श्रम लागत और पैदावार की गुणवत्ता में कमी ने खेती की लागत को बढ़ा दिया है।

है कि कर्ज लेने में पंजाब के किसान लोन के मामले में अन्य राज्यों से आगे हैं।

जिसके तहत पंजाब का एक किसान प्रत्येक साल औसतन 3.4 लाख रुपए तक का कर्ज लेता है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य का किसान प्रत्येक वर्ष औसतन 84000 रुपये और महाराष्ट्र का किसान लगभग 62.000 रुपए का कर्ज प्रत्येक साल लेता है। नाबार्ड ने अपने इस अध्ययन में पाया है कि किसान क्रेडिट कार्ड पर लिए गए कर्ज का डायवर्जन पंजाब में बहुत अधिक है। वहीं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से कृषि कर्ज का डायवर्जन है, लेकिन इस सूची में उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे निचले पायदान में ही है।

ग्राम सभाओं का सहयोग लेते तो सही किसानों की पहचान होती

कर्जमाफी के लिए जो बड़ी राशि खर्च की गई है, उसका भार अन्य सामाजिक क्षेत्रों सेहत, शिक्षा व षेचार्ड के आधारभूत ढांचे पर पड़ा। क्योंकि कर्जमाफी के लिए सरकारों ने इन क्षेत्रों के खर्च में कटौती की है। अध्ययन में यह बात उभरकर सामने आई है कि किसानों की आय बढ़ाए बिना ऐसी योजना लागू करने का कोई औचित्य नहीं है। कारण, किसान फिर उसी स्थिति में आ गए हैं, जिसमें पांच साल पहले थे।

बीज भंडार

हमारे यहाँ पर सभी कम्पनियों के उच्च क्वालिटी के सब्जी बीज एक ही छत के नीचे उचित दाम पर मिले हैं!



ब्रांच: खरगोन/खंडवा/कुशी/बडवाह/राजपुर/अंजड/धामनोद/इंदौर/जबलपुर/मंडलेश्वर/मनावर/बरगी/सनावद/कसरावद

बीज भंडार की फ्रेंचाइसी लेने के लिए संपर्क करे - 8305103633, 7879428271

संपादकीय...

अन्नदाता की अंतहीन व्यथा

भारत की लगभग साठ से सत्तर प्रतिशत आबादी कृषि अथवा उस पर आधारित काम धंधा से जुड़ी हुई है। इसके बावजूद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान मात्र सोलह से सत्रह प्रतिशत ही है। सदियों से अन्नदाता कठोर परिश्रम कर देश का पेट पाल रहा है, लेकिन कई किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि उसके पास न तो तन ढंकने के लिए पर्याप्त वस्त्र है और न ही सिर ढंकने के लिए छत। वह न ही बच्चों की शिक्षा का समुचित प्रबंध कर पाता है और न ही परिवार के किसी बीमार सदस्य का समय पर इलाज करा पाता है। इस आर्थिक युग में तो उसकी स्थिति अब भी पहले से बेहतर नहीं दिखाई देती।

आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी के तीव्र विकास के बावजूद भारतीय कृषि व्यवस्था मौसम आधारित जुआ है। जिस वर्ष प्रकृति मेहरबान होती है उस वर्ष फसल का उत्पादन तो अच्छा होता है, लेकिन जिस वर्ष ऐसा नहीं हुआ उस वर्ष कर्जदार होकर दो जून की रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। जिस वर्ष फसल की अच्छी पैदावार हो जाती है उस वर्ष भी किसान बहुत अधिक खुश नहीं हो पाता है। क्योंकि बाजार में खरीदारों का अभाव होने के कारण उसे उत्पाद की समुचित कीमत नहीं मिल पाती है। कई बार तो उसे बीज, उर्वरक, पारिश्रमिक आदि का लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है। किसान फसल के उत्पादन सहित अनेक व्यक्तिगत कार्यों के लिए कर्ज लिए रहता है तथा उसकी तमाम जरूरतों को पूर्ति फसल उत्पाद की बिक्री पर निर्भर करती है। वह फसल उत्पाद को लंबे समय तक संरक्षित करने में असमर्थ होता है। इसलिए किसान अपने फसल उत्पाद को औने-पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर होता है जबकि वही उत्पाद कुछ समय बाद जमाखोर व्यापारियों द्वारा मोटा मुनाफा कमा कर बहुत ही ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। यानी किसान दोनों ही स्थितियों में मारा जाता है। कई जगह तो कृषि उत्पाद विपणन की पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है।

वैसे तो केंद्र के साथ कृषि राज्यों का विषय है। राज्य सरकारें अपने राजनीतिक लाभ हानि के दृष्टिकोण से कृषि की नीतियां बनाती हैं। किसानों के कल्याण के लिए सार्थक पहल करने के बजाय उनके नाम पर राजनीति करती रहती हैं। इससे किसानों की दशा दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। केंद्र सरकार किसानों के उन्नयन और अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए साठ के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। इससे कुछ हद तक सकारात्मक परिणाम अवश्य मिला। फसल उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि हुई तथा देश खाद्यान्न के लिहाज से आत्मनिर्भर हो गया। हरित क्रांति में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग तथा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। इससे उत्पादन में कुछ हद तक तात्कालिक वृद्धि तो हुई, लेकिन अब धीरे-धीरे उत्पादन स्थिर होता जा रहा है। महंगे उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक के प्रयोग के कारण कृषि उत्पादन लागत बहुत अधिक बढ़ गई है। इसके दुष्प्रभाव से भूमि की उर्वरा शक्ति भी धीरे-धीरे क्षीण हो रही है।

केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकारें कृषि बीमा योजना का कार्यान्वयन तो कर रही हैं परंतु बीमा कंपनियां किसानों को सहायता पहुंचाने के बजाय कागजी खानापूर्ति में ऐसा उलझा देती हैं। सरकारें भी राजनीतिक लाभ के लिहाज से कृषि आपदा राहत की बड़ी-बड़ी घोषणाएं तो करती हैं, लेकिन उसका लाभ कुछ ही किसानों को मिल पाता है। आधुनिक वैज्ञानिक संयंत्रों द्वारा खेती किए जाने से ग्रामीण स्तर पर कृषि क्षेत्र में संलग्न मानवीय श्रम बड़े पैमाने पर बेरोजगार हो रहा है। वैज्ञानिक संयंत्रों द्वारा खेती होने से फसल अपशिष्ट, पराली और भूसे इत्यादि खेत में ही नष्ट कर दिए जाते हैं। इसकी वजह से पशु चारे का अभाव हो रहा है और इससे पशुपालन का संकट उत्पन्न हो रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षित युवा वर्ग खेती के बजाय नौकरी करने के लिए उत्सुक है। यदि कृषि प्रणाली से अन्नदाता का इसी प्रकार पलायन होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब देश में अनाज उत्पादन का संकट उत्पन्न हो जाएगा जो कि भयावह स्थिति होगी इसलिए कृषि की दुर्दशा को सुधारने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों को समन्वित और परिणामदायी प्रयास करना पड़ेगा।

हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य तय कर चुके हैं लेकिन लक्ष्य रखने से कुछ नहीं होता है। इसके लिए ईमानदारीपूर्वक दृढ़ता से पहल करनी होगी व उसका नियमित रूप से मूल्यांकन करना होगा। इस मसले पर आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए भी पर्याप्त प्रबंध करना होगा ताकि अन्नदाता की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के साथ आम आदमी को समुचित मूल्य पर पौष्टिक भोजन संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

प्रतियां पाने, लेख प्रकाशन के लिए संपर्क करें

हलधर किसान, राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र की प्रतियां प्राप्त करने के लिए अपना नाम, डाक पता और फोन नंबर सहित संपर्क करें। साथ ही कृषि, पशुपालन, बागवानी, अनुसंधान जैसे क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, शोध, खेती में नवाचार जैसे लेख प्रकाशन कराना चाहते हैं तो हमें वाट्सएप नंबर- 8305103633, 94254 89337 पर भेजे सकते हैं। हम आपका लेख प्रमुखता से फोटो सहित उचित स्थान पर प्रकाशित करेंगे।

विदेशों में बढ़ रही भारतीय गेहूं की मांग, एमपी का गेहूं बना पहली पसंद

मग्न से 15 अप्रैल तक दो लाख मीट्रिक टन गेहूं विदेशों में निर्यात



हलधर किसान। मग्न के कई जिलों में औसत बारिश के चलते रबी फसलों पर असर देखा गया है। खासकर गेहूं का रकबा कम हुआ है, जिसका असर उत्पादन पर भी पड़ा है। बावजूद इसके रूस, यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के चलते विदेशों में गेहूं की मांग बढ़ने से निर्यात भी बढ़ा है। विदेशों में गेहूं निर्यात करने में प्रदेश अक्वल है। मग्न का गेहूं विदेशों में पसंद किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते सालों के मुकाबले इस साल गेहूं एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ा है। विदेशों में मध्यम क्वालिटी के गेहूं की भारी मांग है।

जानकारी अनुसार सीहोर रायसेन गुना और विदिशा से 12 टन गेहूं सऊदी अरब और वियतनाम देशों में भेजा गया भारतीय मध्य प्रदेश के गेहूं की डिमांड विदेश में किस स्तर की है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष गेहूं निर्यात लगभग 3 गुना बढ़ गया है। इसका सीधा फायदा किसानों को ही मिल रहा है। अब मंडियों में गेहूं के ऊंचे दाम पर बिकवाली हो रही है। जानकार बताते हैं कि यही स्थिति आगे लंबे समय तक बनी रहेगी। बाजार में बढ़े दामों का असर समर्थन मूल्य पर खरीदी पर भी देखा जा रहा है, किसान शासकिय खरीदी में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।

गेहूं बना मुनाफे का कारोबार

अंतरराष्ट्रीय बाजार में मध्यम क्वालिटी के गेहूं के भाव 2400 से 2700 के बीच लगातार बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2021 में खाड़ी के देश एक नाम और वियतनाम और सऊदी अरब में 3.70 लाख टन गेहूं निर्यात हुआ था। गुना में गेहूं के एक बड़े निर्यातक मनीष अग्रवाल (महूवाले) के अनुसार इस बार 50 हजार टन गेहूं निर्यात की होने की संभावना है। हमने रेलवे से 16 रैंक की डिमांड की है। अब तक सिर्फ 2 रैंक ही मिली हैं। पिछले साल यहां से 20 हजार टन गेहूं विदेशों में भेजा गया था। इसी प्रकार प्रदेश के सीहोर से 2.5 लाख टन, रायसेन से 4 लाख टन और विदिशा से 5 लाख टन गेहूं निर्यात किया जाएगा। कुल मिलाकर इन चार बड़ी मंडियों से 12 लाख टन गेहूं इस बार बाहर भेजा जा रहा है यानी पिछले साल के निर्यात से 8.30 लाख टन ज्यादा।

गेहूं निर्यात कारोबारी अग्रवाल बताते हैं कि 2021 के मुकाबले

मध्य प्रदेश के गेहूं की विदेशों में मांग है और यही कारण है कि राज्य से वर्ष 2021.22 और 2022.23 में 15 अप्रैल तक दो लाख मीट्रिक टन गेहूं का विदेशों में निर्यात किया गया। राज्य में पैदा होने वाले गेहूं की गुणवत्ता और बंपर पैदावार के चलते विदेशों में निर्यात बढ़ा है। वर्ष 2021.22 एवं 2022.23 में 15 अप्रैल तक दो लाख चार हजार 771 मीट्रिक टन गेहूं का विदेशों में निर्यात किया गया। इसमें इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, हरदा, छिंदवाड़ा और दतिया से बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, यूएई, विएतनाम को गेहूं निर्यात किया गया। जबकि भोपाल, गुना, टीकमगढ़, मुरैना, ग्वालियर और अन्य जिलों से इजिप्ट, फिलीपींस, जिम्बाब्वे और तंजानिया में गेहूं निर्यात की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

बताया गया है कि गेहूं के निर्यात से लगभग 460 करोड़ आठ लाख रुपए का विदेशी राजस्व भी प्राप्त हुआ है। इस अवधि में सर्वाधिक गेहूं इंदौर से 97 हजार 887 मी.टन एवं अन्य कुछ जिलों से न्यूनतम तीन हजार 370 मी. टन निर्यात किया गया। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाह लाल सिंह ने बताया कि विगत एक माह में मध्यप्रदेश से देश के विभिन्न आठ स्थानों पर गेहूं के 87 रैंक भेजे गए। मंत्रि.परिषद द्वारा लिए निर्णय के बाद निर्यातकों के पंजीयन हेतु ऑनलाईन पोर्टल प्रारंभ किया गया है। वहीं रबी फसलों की खरीदी की प्रक्रिया जारी है। रबी उपार्जन में 27 लाख 24 हजार 999 मीट्रिक टन रबी फसलों के लिए पंजीयन कराया गया जिसमें गेहूं 19 लाख 81 हजार 506 ए चना चार लाख 57 हजार 680, मसूर एक लाख 14 हजार 876 एवं एक लाख 70 हजार 937 मीट्रिक टन सरसों फसल के लिए पंजीयन शामिल है। यह पंजीयन 5017 उपार्जन केंद्रों पर कराया गया। खाद्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के एक लाख 85 हजार 366 कृषकों ने अपनी फसलों के विक्रय के लिए पंजीयन कराया है। इसमें से एक लाख 70 हजार 48 किसानों ने गेहूं, 15 हजार 318 किसानों ने चना विक्रय के लिए पंजीयन कराया।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग की वजह से देश का गेहूं निर्यात वित्त वर्ष 2022.23 में एक करोड़ टन के पार जाने की उम्मीद है। गेहूं निर्यात 2021.22 में 70 लाख टन (15.000 करोड़ रुपये से अधिक) को पार कर गया था जबकि 2020.21 में यह आंकड़ा 21.55 लाख टन रहा था। वर्ष 2019.20 में यह महज दो लाख टन (500 करोड़ रुपये) रहा था। गोयल ने संवाददाताओं से कहा, हम बड़े पैमाने पर गेहूं निर्यात जारी रखेंगे और उन देशों की जरूरतें पूरी करेंगे जिन्हें संघर्षरत क्षेत्रों से आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। मेरा मानना है कि इस बार हमारा गेहूं निर्यात बहुत आसानी से 100 लाख टन से पार निकल जाएगा। गेहूं की वैश्विक आपूर्ति में रूस और यूक्रेन की करीब एक चौथाई हिस्सेदारी रहती आई है। इन दोनों देशों में गेहूं की फसल इस साल अगस्त और सितंबर में पक जाएगी। किसान भी गेहूं का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं और गुजरात तथा मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों से पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक आयात हो रहा है। गेहूं निर्यात के बारे में मिस्त्र से भारत की अंतिम दौर की बातचीत चल रही है जबकि चीन और तुर्की के साथ भी संवाद चल रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि अन्य बंदरगाहों से निर्यात सुगम बनाने के लिए वाणिज्य विभाग, खाद्य एवं जन सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। ज्यादातर निर्यात कांडला बंदरगाह से होता है। सारंगी ने बताया कि विशाखापटनम, काकीनाडा और न्हावा शेवा जैसे बंदरगाहों से गेहूं निर्यात शुरू करने के लिए रेलवे से बात चल रही है।

गेहूं निर्यात 2021.22 में 70 लाख टन (15.000 करोड़ रुपये से अधिक) को पार कर गया था अब उम्मीद की जा रही है इस साल यह 1 करोड़ टन से भी अधिक रह सकता है यानी गेहूं निर्यात के मामले में भारत हर गुजरते साल के साथ एक नया मुकाम हासिल कर रहा है रूस, यूक्रेन युद्ध की वजह से भी गेहूं के निर्यात में तेजी देखने को मिल रही है

इस बार अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं का भाव 300 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा खुला था। हालांकि बीते एक महीने के दौरान इसमें बार-बार उतार चढ़ाव नजर आते रहे। उन्होंने बताया कि विदेशों में किसी भी खास गेहूं की डिमांड नहीं रहती। वहां गेहूं का इस्तेमाल तैयार खाद्य पदार्थों के लिए होता है। इसलिए मध्यम क्वालिटी का गेहूं ही ज्यादा मांगा जाता है।

किसान और व्यापारियों के लिए सही समय

कृषि निर्यात मामलों के जानकारों का कहना है कि सरकार अगर निर्यात मामलों को लेकर सजग हो जाए तो से किसानों के साथ साथ निर्यातकों के लिए भी यह अच्छा समय है। ग्लोबल मार्केट में अप्रैल-मई तक गेहूं की मांग बनी रहेगी। ऐसे में आने वाला दो-तीन महीने भारत के निर्यात के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस बार भारत से गेहूं का निर्यात 70 लाख टन के स्तर को पार कर सकता है। इस बार इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, हरदा, छिंदवाड़ा, दतिया से बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, यूएई, वियतनाम जैसे देशों को बंपर निर्यात किया जा रहा है। वहीं भोपाल, गुना, टीकमगढ़, मुरैना, ग्वालियर और अन्य जिलों से मिस्त्र, फिलीपींस, जिम्बाब्वे और तंजानिया को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करने की संभावना है।

900 करोड़ रुपए की तीन सिंचाई परियोजनाओं को मिली मंजूरी, किसानों को होगा फायदा

हलधर किसान। मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए तीन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैसा कि बिना पानी के खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वहीं साल दर साल भूजल स्तर काफी नीचे गिर जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए तीन परियोजनाओं को मंजूरी देना काफी महत्वपूर्ण निर्णय है। बीते दिनों मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें मंत्रिपरिषद ने रीवा, बुरहानपुर और सिंगरौली में 900 करोड़ रुपए से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। इन परियोजनाओं से 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

रीवा में त्योंथर माइक्रो सिंचाई परियोजना लागत राशि 89 करोड़ 83 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना से त्योंथर तहसील के 52 ग्रामों की 7600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। बुरहानपुर जिले की पांगरी मध्यम (होज) सिंचाई परियोजना लागत राशि 145 करोड़ 10 लाख रुपए की सिंचाई क्षमता 4400 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना से खकनार तहसील के 10 ग्रामों को भूमिगत पाइप लाइन से सूक्ष्म सिंचाई (होज) पद्धति से सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।

मंत्रिपरिषद ने सिंगरौली जिले की सिंगरौली एवं माड़ा तहसील के 38 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत पाइप लाइन से उच्च दाब पर सूक्ष्म सिंचाई (स्प्रिंकलर) पद्धति के द्वारा 113 ग्रामों में सिंचाई सुविधा के लिए रिहन्द सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागत राशि 672 करोड़ 25 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

सीएम की अध्यक्षता में हुई मंत्री. परिषद की बैठक



कयामपुर.सीतामऊ को भी मिली स्वीकृति

राज्य शासन द्वारा मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की महत्वाकांक्षी कयामपुर.सीतामऊ दाबयुक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग की पहल पर 2374 करोड़ रुपए लागत की इस योजना को 5 अप्रैल 2022 को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई थी। बता दें कि इस परियोजना से मंदसौर जिले के 252 गांवों का एक लाख 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। योजना के पूर्ण होने पर सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव और खेत तक चबल का पानी पहुंचेगा।

इससे किसानों की आर्थिक समृद्धि होगी।

राज्य सरकार का फोकस माइक्रोइरीगेशन पर रहेगा। किसानों से सूक्ष्म सिंचाई (स्प्रिंकलर) पद्धति अपनाने पर जोर दिया जाएगा ताकि बूंद-बूंद पानी का इस्तेमाल खेती के लिए किया जा सके। बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार की ओर से सूक्ष्म सिंचाई के तहत ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अपनाने वाले किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके अलावा किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है जिसका लाभ मध्यप्रदेश के किसानों को भी मिल रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार 1.71 लाख हेक्टेयर भूमि तीन महीने में बनायेगी खेती योग्य



हलधर किसान। उत्तर प्रदेश में आगामी 100 दिनों में कुल 1.71.186 हेक्टेयर भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में किसानों को लाभ होगा। इससे खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल बढ़ने की आशा है। मुख्यमंत्री योगी के समक्ष प्रस्तुतीकरण में कृषि विभाग के सभी घटकों ने किये जाने वाले कार्यों का ब्योरा दिया। भूमि सुधार के लिए चलाई जा रही पं दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत आगामी 100 दिनों में 477.33 रुपए करोड़ का खर्च प्रस्तावित है वहीं इस योजना में पिछले पांच वर्षों में 1.41.840 हेक्टेयर भूमि उपजाऊ कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित की गई है। इस योजना पर लगभग 291.70 करोड़ रुपए का खर्च आया है।

एक सर्वेक्षण के आधार पर परियोजना क्षेत्रों में 8.58 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन में वृद्धि हुई है। लगभग 48.53 प्रतिशत आय में वृद्धि देखी गई और भूगर्भ जल स्तर में 1.42 मीटर की वृद्धि परिलक्षित हुई। जैविक क्लस्टर को बढ़ावा देने की नीति के अंतर्गत, वर्ष 2021.22 तक 4784

क्लस्टरों 95680 हेक्टेयर से 1.75 लाख किसानों को जोड़ा गया है। इनमें, नमामि गंगे योजना के तहत 3309 क्लस्टर, पीकेवीवाई में 1195 क्लस्टर व हमीरपुर जैविक खेती योजना में 280 क्लस्टर हैं। इनमें योजना के अंतर्गत भूमि का क्षेत्रफल लगभग 95.680 हेक्टेयर है। इस नीति में तीन वर्षीय कार्यक्रम के अंतर्गत, एक क्लस्टर में लगभग 50 किसान जोड़े जाते हैं और प्रति क्लस्टर तीन वित्तीय वर्ष के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान है।

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कार्ययोजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा संवर्धित मिशन प्राकृतिक खेती के अंतर्गत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना को प्रदेश के 35 जनपदों में लागू किया जाएगा जिसके लिए विकास खंड स्तर पर 500 से 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल के क्लस्टर का गठन होगा। यह योजना खरीफ 2022 से शुरू की जाएगी और इस पर 82.83 करोड़ रुपये; केंद्र पोषित खर्च किये जाएंगे। बुंदेलखंड के समस्त जनपदों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का क्रियान्वयन भी तेज किया जाना का लक्ष्य रखा गया है और मई माह में राज्य.स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

पाराली प्रबंधन के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय काम किया गया है। किसानों को इससे राहत देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये। पिछले पांच वर्षों में प्रति लाख हेक्टेयर धान क्षेत्रफल में पाराली जलाने की औसत घटनाओं की संख्या उत्तर प्रदेश में मात्र 71, व उप्र.एनसीआर क्षेत्र में 132 दर्ज की गई। इसके अपेक्षा पंजाब में यह संख्या 2264 व हरियाणा में 452 दर्ज की गई थी। राज्य में पाराली को गौशालाओं में चारे के रूप में आपूर्ति किये जाने के लिए पाराली दो, खाद लो अभियान भी सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है।

अब देश के किसानों को राहत देने के लिए उर्वरक सब्सिडी पर संशोधन करने की तैयारी में केंद्र सरकार

उर्वरकों के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। इस बीच अब केंद्र सरकार इसको लेकर एक्शन मोड में आ गई है। जिसके तहत केंद्र सरकार आगामी खरीफ सीजन में अब किसानों को राहत देने के लिए उर्वरक सब्सिडी पर संशोधन करने की पूरी तैयारी कर रही है। इसको लेकर उर्वरक विभाग की तरफ से 19 अप्रैल को एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया है। जिसमें यह सारी जानकारी दी गई है। उर्वरक विभाग की तरफ से यह प्रेजेंटेशन कृषि व किसान कल्याण विभाग की ओर से आयोजित खरीफ अभियान 2022.23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिया गया है। इस सम्मेलन में देश के कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। इस दौरान उर्वरक विभाग ने उर्वरक सब्सिडी पर संशोधन की सारी जानकारी दी है।

बस कैबिनेट मंजूरी का इंतजार

अंग्रेजी अखबार मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक उर्वरक विभाग ने प्रेजेंटेशन में कहा कि उर्वरक और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें जनवरी 2021 से लगातार बढ़ ही रही हैं साथ ही प्रेजेंटेशन में कहा गया गया है कि एक अंतर.मंत्रालयी समिति ने खरीफ 2022 के लिए नाइट्रोजन एंफोस्फोरस एं पोटेशियम और सल्फर के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों में संशोधन की सिफारिश भी की है जो विशेष रूप से सिर्फ इस बार के लिए लागू होगी और यह सब्सिडी मार्च 2022 में उर्वरकों की औसत अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर विभाग द्वारा तय होगी मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेजेंटेशन में कहा गया है कि खरीफ 2022 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों पर अब सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है।

देश में अप्रैल में डीएपी की कीमत में हुई लगभग 150 रुपये की बढ़ोतरी

बता दें कि भारत की प्रमुख सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने बीते 1 अप्रैल को उर्वरकों की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी की थी जो जिसके तहत ने डाय अमोनियम फॉस्फेट और एनपीके की कीमतों में ही इजाफा किया था। इसमें डीएपी खाद की कीमत में 150 रुपये की बढ़ोतरी की थी। इससे पूर्व भी उर्वरक बनाने वाली अन्य कंपनियों ने उर्वरकों की कीमतों के दाम में कुछ इजाफा किया था। ऐसे में अब किसानों को खेती की लागत बढ़ने की चिंता सता रही है अतः अब खरीफ सीजन बिल्कुल करीब है ऐसे में उर्वरकों की बढ़ी कीमतें किसानों का गणित बिगाड़ सकती हैं। इसका असर किसानों की आर्थिक स्थिति पर होगा।

रूस.यूक्रेन युद्ध के कारण उर्वरकों की वैश्विक कीमतों में तेजी

उर्वरकों के दाम में बीते दिनों हुई बढ़ोतरी का मुख्य कारण रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को बताया जा रहा है। असल में रूस से ज्यादा मात्रा में उर्वरकों का कच्चा माल आता है, ऐसे में युद्ध के मद्देनजर अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है तो रूस की पूरी सप्लाई चैन बहुत प्रभावित हुई है। इस वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उर्वरकों के दाम में एकदम बढ़ोतरी हुई है।

रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देगी मध्य प्रदेश सरकार, प्राकृतिक कृषि बोर्ड का जल्द होगा गठन

खेती के कुछ हिस्से में प्राकृतिक खेती जरूर करें किसान, कार्यशाला में निकला निष्कर्ष



हलधर किसान। प्राकृतिक कृषि पर आयोजित कार्यशाला सिर्फ कर्मकांड नहीं है, यह कृषि की दशा और दिशा बदलने का महायज्ञ है। प्रदेश में मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड का तत्काल गठन किया जाएगा। प्राकृतिक खेती की तकनीक की जानकारी देने के लिए प्रदेश के किसानों को पुस्तक उपलब्ध कराई जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित शून्य बजट प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यशाला में कही।



उन्होंने कहा मैं स्वयं अपनी 5 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती शुरू कर रहा हूँ। प्रदेश के सभी किसानों से अपील की कि उनके पास जितनी भी कृषि भूमि है, उसमें से कुछ क्षेत्र में वे प्राकृतिक खेती प्रारंभ करें। इससे होने वाले लाभ से दूसरे किसान भी प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित होंगे। धरती मां की उर्वरा क्षमता बनाए रखने के लिए हमें सचेत होना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश जैविक खेती में अग्रणी राज्य है।

अनुपात में हमें धरती मां को जल देना भी होगा। यह आने वाली पीढ़ी को बेहतर धरोहर सौंपने का प्रयास है। धरती के स्वास्थ्य, कृषकों की स्थिति और निरोगी जीवन के लिए प्राकृतिक खेती ही वैकल्पिक मार्ग है। उन्होंने कहा कि यह वास्तविकता है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद की आवश्यकता थी, उत्पादन बढ़ाना जरूरी था परंतु समय के साथ इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक के अधिक उपयोग और खेती में पानी की अधिक आवश्यकता आदि से खेती की लागत बढ़ती जा रही है। उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन खर्च भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। खेती के इस दुष्चक्र का वैकल्पिक मार्ग खोजना होगा।

नहीं संभलते तो आगामी 50 साल में बंजर हो जाएगी जमीनें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि खेतों में जिस तरह से हम यूरिया और डीएपी का उपयोग कर रहे हैं, उससे आने वाले 50 साल में भूमि बंजर हो जाएगी। प्रतिवर्ष यूरिया और डीएपी की खपत बढ़ती जा रही है। इससे किसानों की लागत बढ़ने के साथ उपज की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। धरती की सेहत खराब हो रही है और आमजन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इससे बचने का एकमात्र उपाय प्राकृतिक खेती है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ेगी और किसानों की लागत भी घटेगी।

ऐसे होती है प्राकृतिक खेती

आचार्य देवव्रत ने बताया कि इसके लिए देशी नस्ल की गाय होनी चाहिए। उससे जो गोबर और गोमूत्र मिलता है, उसे दो सौ लीटर के ड्रम में 170 लीटर पानी में मिलाकर रखना है। डेढ़ से दो किलोग्राम गुड़ और इतना ही बेसन मिलाया है। सुबह और शाम इसे लकड़ी से घुमाएँ। चार दिन

में जीवामृत तैयार हो जाएगा। सिंचाई के साथ इसका छिड़काव करें। यह यूरिया का काम करेगा। इसी तरह बीजामृत तैयार होता है। इससे बीजों को शुद्ध किया जाता है और खेतों में डालने पर यह डीएपी का काम करता है। खेतों में खाली स्थान को ढकना भी चाहिए। इससे नमी बनी रहेगी और पानी कम लगेगा।

वन ग्राम समिति की मेहनत से लौट रहा है वनों का खोया वैभव



वन विभाग ने माइक्रो प्लानिंग कर ग्राम वन समितियों के सहयोग से जंगलों की बहाली पर विशेष ध्यान दिया है, जिसके सुखद परिणाम मिलने लगे हैं। मंडला जिले का मनेरी वन ग्राम स्टाक मेपिंग (वर्ष 2004.14) क्षेत्र वनस्पति से रहित था और आरडीएफ (वन पुनर्घनत्विकरण) के लिये चुना गया था। मनेरी ग्राम वन समिति का गठन कर उसे 186.92 हेक्टेयर वन प्रबंधन का काम सौंपा गया था। औद्योगिक क्षेत्र के आसपास होने के कारण यह वन क्षेत्र गंभीर जैविक दबाव में था। बावजूद इसके स्थानीय समुदायों ने अवैध कटाई और चराई के खिलाफ वनों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वर्ष 2003.4 और 2005.6 के बीच यहाँ जंगल बहाली का काम शुरू हुआ। इस काम में ग्राम वन समिति मनेरी का नेतृत्व कर रही महिला सुश्री कल्लू बाई माको ने वन संरक्षण और प्रबंधन के लिये समुदाय को संगठित करने में सराहनीय भूमिका निभाई। ग्राम वन समुदाय के अथक प्रयास और दृढ़ संकल्प के चलते आज यह क्षेत्र वन से बहाल हो गया है। इतना ही नहीं, बीते 2 सालों में समुदाय ने 3 हजार 526 सागौन और 31 ईंधन के ढर की कटाई कर लाभ भी कमाया है।

जनजातीय ग्राम वन समिति ने बहाल किया 192 हेक्टेयर में जंगल

वन विभाग ने स्थानीय समुदायों को वन प्रबंधन और उनकी बहाली में शामिल करते हुए प्रदेश के खाली वन क्षेत्रों को वन सम्पदा से समृद्ध करने में कामयाबी हासिल की है। झाबुआ जिले की बड़ी नाल्दी ग्राम वन समिति को लगभग 15 साल पहले 192 हेक्टेयर खाली वन क्षेत्र को बहाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ग्राम वन समिति के सदस्य और ग्रामीणों द्वारा सालों से किये गये अथक प्रयासों से इस क्षेत्र का वन वैभव पुनः लौट आया है। जनजातीय समुदाय की आजीविका में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन की बहाली से आजीविका के संसाधन भी बढ़ने लगे हैं। वनों के कम होने से पारिस्थितिकी तंत्र में भी असंतुलन जैसी जलवायु समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। वनों की बहाली से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने का एक उचित और स्थायी समाधान मिल गया है।

धरती की उर्वरा क्षमता बनाए रखने हमें रहना होगा सचेत

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रकृति का शोषण नहीं दोहन करने का विचार दिया है। यह भविष्य के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए दिया गया मंत्र है। रासायनिक खाद और कीटनाशक के उपयोग के परिणामस्वरूप धरती का स्वास्थ्य निरंतर प्रभावित हो रहा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती मां की उर्वरा क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें सचेत रहना होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यह धरती केवल मनुष्यों के लिए नहीं, अपितु कीट-पतंगों और जीव-जंतुओं के लिए भी है। हमने कीटनाशक के अंधाधुंध उपयोग से कीट मित्रों को समाप्त कर दिया है और हमारी नदियाँ भी प्रभावित हुई हैं।

निरोगी जीवन के लिए प्राकृतिक खेती ही विकल्प

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की संकल्पना के अनुरूप जल-संरक्षण के लिए प्रदेश में जलाभिषेक अभियान शुरू किया गया है। हम जितना जल धरती से ले रहे हैं। उस

नहीं संभलते तो आगामी 50 साल में बंजर हो जाएगी जमीनें

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि खेतों में जिस तरह से हम यूरिया और डीएपी का उपयोग कर रहे हैं, उससे आने वाले 50 साल में भूमि बंजर हो जाएगी। प्रतिवर्ष यूरिया और डीएपी की खपत बढ़ती जा रही है। इससे किसानों की लागत बढ़ने के साथ उपज की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। धरती की सेहत खराब हो रही है और आमजन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इससे बचने का एकमात्र उपाय प्राकृतिक खेती है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ेगी और किसानों की लागत भी घटेगी।

आचार्य देवव्रत ने बताया कि वे स्वयं पहले रासायनिक खादों का उपयोग खेतों में

करते थे। एक दिन कीटनाशक का छिड़काव करते समय मजदूर चक्कर खाकर खेत में गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले गए। उसका जीवन तो बच गया पर यह विचार आया कि अपने गुरुकुल में देशभर के एक हजार 400 बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें जो भोजन दिया जा रहा है, उसमें तो जहर है। तब पांच एकड़ में जैविक खेती प्रारंभ की। पहले साल कुछ उत्पादन नहीं मिला। दूसरे साल 50 प्रतिशत उत्पादन और तीसरे साल में 80 प्रतिशत उत्पादन हुआ लेकिन लागत और मेहनत कम नहीं हुई। इसके बाद प्राकृतिक खेती को अपनाया। पहले साल से ही उत्पादन मिला और यह साल-दर-साल बढ़ता गया। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इसे बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। इससे भूमि में सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते हैं जो भूमि का उपजाऊ बनाते हैं। जल संग्रहण की क्षमता भी बढ़ती है।

पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा. किसान भाई-बहनों पर देश को गर्व, वे सशक्त होंगे तो नया भारत समृद्ध होगा

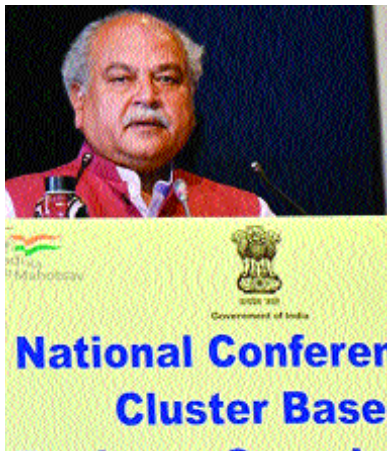


पीएम मोदी ने कहा कि देश का किसान जितना सशक्त होगा, नया भारत उतना ही समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि पीएम किसान और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह किए गए एक ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा, 'हमारे किसान भाई-बहनों पर देश को गर्व है'। ये जितना सशक्त होंगे, नया भारत भी उतना ही समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। इस ट्वीट के साथ उन्होंने कुछ आंकड़े भी साझा किए। प्रधानमंत्री ने यह बातें तब कही हैं जब देश का किसान खेतों में पसीना बहा रहा है और रबी फसलों की कटाई के बाद खरीफ की तैयारी में जुटा हुआ है। आंकड़ों के माध्यम से बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.3 करोड़ किसानों के खाते में 1.82 लाख करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए गए हैं। सभी किसानों के लिए 6 हजार रुपये की सालाना मदद की जा रही है। कृषि इंफ्रस्ट्रक्चर फंड का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि कृषि से संबंधित आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की लोन की सुविधा मुहैया कराई गई है।

सरकार की योजनाओं से किसानों को मिल रही मदद
साथ ही बताया गया है कि 11 हजार 632 प्रोजेक्ट के लिए 8585 करोड़ रुपये के लोन की मंजूरी हो चुकी है। इस फंड को कोविड महामारी के दौर में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जारी किया गया था। वहीं ई.नाम, राष्ट्रीय कृषि बाजार का चर्चा करते हुए कहा गया है कि देश भर की मंडियों का डिजिटल एकीकरण किया जा रहा है। ई.नाम पर 1.73 करोड़ किसानों का पंजीकरण हो चुका है और इस प्लेटफॉर्म के तहत 1.87 लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है। अपने बयान में पीएम मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। हर बार हर किस्त समय से, हर साल हजारों करोड़ रुपये का ट्रांसफर, बिना किसी बिचौलिये के, बिना किसी कमीशन के, पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। छोटे किसानों ने इस राशि से अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद रहे हैं, अच्छी खाद और उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

मई में जारी हो सकती है 11वीं किस्त
यहां बताना जरूरी है कि अभी तक किसानों को पीएम किसान की 10 किस्त मिल चुकी है। योजना के तहत पंजीकृत किसानों को 11वीं किस्त का इंतजार है। 11वीं किस्त जारी करने के लिए कृषि मंत्रालय की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और आने वाले दिनों में पैसे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। बीते साल 15 मई को किस्त जारी हुई थी। ऐसे में उम्मीद है कि मई के महीने में किसी दिन प्रधानमंत्री 11वीं किस्त जारी करेंगे।

10 हजार एफपीओ की योजना कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति का सूत्रपात. केंद्रिय कृषि मंत्री तोमर



हलधर किसान। देश में बनाए जा रहे 10 हजार कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) की स्कीम कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति का सूत्रपात है। इस क्रांति के माध्यम से, बुआई से बाजार तक किसानों को सक्षम बनाकर उनकी आमदनी बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह बात केंद्रिय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) के दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान बतौर मुख्य अतिथि कही।

केंद्रिय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि एफपीओ से किसानों को समृद्ध बनाने के लिए सीबीबीओ को हर जतन करना होगा। एफपीओ की परिकल्पना तब पूरी होगी, जब एफपीओ बनने के बाद उसका लाभ किसानों को मिलने लगे तथा केसर की तरह उसकी खुशबू फैले और सारे किसान कहें कि हमें भी एफपीओ से जोड़िए व आगे नए एफपीओ गठन के लिए सरकार से मांग हो। सीबीबीओ को सरकार साधन दे रही है, जिससे अच्छे परिणाम

आना चाहिए। सीबीबीओ इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि वे इस विषय में विशेषज्ञ हैं। जागरूकता फैला सकते हैं, किसानों को खेती में टेक्नालाजी दे सकते हैं, किसान अच्छा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करें, इस दृष्टि से मार्गदर्शन कर सकते हैं और किसानों को वाजिब दाम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। श्रेष्ठ एफपीओ के गठन के लिए सीबीबीओ को सभी को साथ लेकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में पहले लगभग 7 हजार एफपीओ बने थे, लेकिन अधिकतर टिकाऊ नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई योजना लेकर आए। एफपीओ छोटे किसानों के संगठन है। इस पूरी योजना पर सरकार 6.865 करोड़ रुपये खर्च करेगी। देश में लगभग 86 प्रतिशत छोटे किसान हैं, जिन्हें एफपीओ के माध्यम से आदान उपलब्ध कराने से लेकर प्रोसेसिंग व उपज की बाजार में उचित दाम पर बिक्री में सहयोग जैसी सुविधाएं दिलाना सरकार का उद्देश्य है। एफपीओ किसानों की संगठन शक्ति के प्रतीक है। श्री तोमर ने कहा कि आज हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसमें हमें पुराने संकल्प पूरे करना है और नए संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। देश में खेती को उन्नत बनाने के अंतर्गत दूर करने व किसानों की माली हालत सुधारने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार हरसंभव उपाय कर रही है। किसानों की सुविधा के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी की गई हैं। एक लाख करोड़ रुपये के कृषि इंफ्रस्ट्रक्चर फंड से किसानों के लिए सरकार गांव-गांव सुविधाएं जुटाने के लिए प्रयत्नशील है। ऐसी कई योजनाएं हैं।

केंद्रिय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि एफपीओ की

स्कीम में सीबीबीओ महत्वपूर्ण कड़ी है, ये ठान लें तो उद्देश्य की प्राप्ति जरूर होगी। कुल मिलाकर, उद्देश्य यह है कि किसानों को लाभ पहुंचे। श्री चौधरी ने एफपीओ से अधिकाधिक किसानों को जोड़े जाने की अपेक्षा जताई और कहा कि इस संबंध में सरकार द्वारा बनाई गई गाइड लाइन के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी भी एफपीओ के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जाना चाहिए।

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) की एमडी श्रीमती नीलकमल दरबारी ने सम्मेलन की भूमिका प्रस्तुत की। केंद्रिय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अभिलक्ष लिखी ने सीबीबीओ से सरकार की अपेक्षाएं बताई। संयुक्त सचिव डा. श्रीमती विजय लक्ष्मी ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने बताया कि योजना में पहले से ही प्रावधानित तीन क्रियान्वयन एजेंसियों, नाबार्ड, एसएफएसी व एनसीडीसी सहित 13 क्रियान्वयन एजेंसियों को नामित किया गया है। नाबार्ड के चेयरमैन जीआर चिंताला ने स्कीम को लेकर कुछ सुझाव दिए। राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी ईवाय के पाटनर श्री सत्यम शिवम सुंदरम ने प्रेजेंटेशन दिया, वहीं व्यवहार्यता अध्ययन और सामाजिक गतिशीलता दृष्टिकोण, व्यापार योजना निर्माण दृष्टिकोण तथा ब्रांडिंग व मार्केटिंग दृष्टिकोण पर सीबीबीओ व अन्य एजेंसी ने प्रस्तुति दी। इस अवसर पर एसएफएसीए नाबार्ड, एनसीडीसी, नैफेड, एपीएमएएसए ई एंड वाई, एक्सजे डेवलपमेंट सर्विसेज, ग्रांट थानटन व अन्य कंपनियों के अधिकारी व देशभर से आए सीबीबीओ के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

इंदौर के दो प्रतिष्ठानों में मिले बीटी कॉटन के अवैध पैकेट, कृषि विभाग ने दर्ज कराई एफआईआर

खरीफ सीजन के पहले अवैध बीज के कारोबारी सक्रिय

हलधर किसान। आगामी खरीफ सीजन तैयारियों के बीच इंदौर में बीटी कॉटन की प्रचलित किस्म के अवैध बीज पैकेट मिलने से कृषि विभाग सहित प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। यह अवैध बीज पैकेट कृषि विभाग के निरीक्षण के दौरान सामने आए जिस पर सख्त एक्शन लेते हुए कलेक्टर के निर्देश पर दो दुकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

उप संचालक कृषि एसएस राजपूत ने बताया कि जिले में खाद-बीज के अवैध क्रय-विक्रय तथा भंडारण करने वालों के



फोटो सोशल मीडिया

विरुद्ध कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है। रावजी बाजार थाना में आरोपी मेसर्स पाटीदार सीड्स कॉर्पोरेशन प्रालि राजीव काका मार्केट स्टेट हाईवे रोड बडाली जिला सांबरकाठा (गुजरात) एवं एक्सपर्ट जेनेटिक्स

प्रालि. अगुर (गुजरात) के प्रोपराईटर भरत भाई पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह प्रकरण बीज अधिनियम 1966 की धारा 3.7 एवं 17 बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 4 एवं 5 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम



1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत उल्लंघन होकर प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बताया गया कि 20 अप्रैल 2022 को मेसर्स सनावद बेडिया ट्रांसपोर्ट लोहा मण्डी इंदौर के ऑफिस और गोदाम,

नागिनलाल राजमल भण्डारी ट्रांसपोर्ट 15/1 नवलखा मेनरोड लोहा मण्डी इंदौर एवं हिन्दुस्तान केरियर कांपोरेशन आनंद चेम्बर लोहा मण्डी इंदौर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान मेसर्स पाटीदार सीड्स कॉर्पोरेशन प्रालि एवं एक्सपर्ट जेनेटिक्स प्रालि के विभिन्न किस्मों के बीटी कपास बीज के अवैध पैकेट पाए गए। इनको जब्त किया गया और दोनों प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया। उल्लेखनीय है कि बीटी कॉटन कपास किसानों की पहली पसंद मानी जाती है, यही कारण है कि आगामी सीजन को देखते हुए कालाबाजारी और अवैध निर्माता भी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं, हालांकि प्रशासन की सतर्कता से यह मामला उजागर हो गया है।

वनवासियों को जंगल की मालिकी दिलवाने वाला मप्र देश का पहला राज्य: केन्द्रीय गृह मंत्री शाह



सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज ने कही ये बातें

. सभा के दौरान सीएम ने कई घोषणाओं को गिनाते हुए कहा कि हमने जबलपुर में वादे किए थे वे एक-एक करके जमीन पर उतार रहे हैं और गरीबों की जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। 89 जनजातीय ब्लॉक में राशन की गाड़ी भेजने कहा था, मुझे कहते हुए खुशी है वह राशन बंटना अधिकांश स्थानों पर प्रारंभ हो गया है।

. प्रदेश में पेसा एक्ट लागू करने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ये जमीन और जंगल आपके हैं, सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार एक क्रांतिकारी कदम है। जंगल से जो लकड़ी निकलेगी, वह आपके आय का साधन होगी।

. गरीब की जिंदगी बदलने के लिए मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू किया जा रहा है। प्रदेश के जंगल पर अधिकार वनोपज आश्रित जनजातीय भाई-बहनों का है। आपके जीवन में बदलाव ही हमारा लक्ष्य है।

. जंगल बदलने की प्रक्रिया ग्राम सभा करेगी, मप्र ने अपने वनवासी भाई-बहनों को जंगल सौंपने का काम किया है। वन विभाग केवल सहयोग करने का काम करेगा।

अब वन ग्राम राजस्व ग्राम बन जाने से आपके पास जो जमीन है उसके खाते बनेंगे, किस्तबंदी होगी, खसरा-नक्शा आपको प्राप्त होंगे, नामांतरण बंटवारा होगा।

ये अभी तक नहीं होता था वन ग्राम में रहने वाले किसान भाइयों अब प्राकृतिक आपदा होने पर आपको पर्याप्त मुआवजा देने का अधिकार होगा।

तेंदूपत्ते का बोनस बांटने का काम शुरू किया है। आज 125 करोड़ रुपये 22 लाख तेंदूपत्ता तोड़ने वाले गरीबों के खाते में जाना प्रारंभ होगा, लाभांश आपको होगा।

हलधर किसान। भोपाल के जबूरी मैदान में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वन समितियों का सम्मेलन का आयोजन किया गया है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का मुख्यमंत्री चौहान ने पारंपरिक जनजातीय स्वागत पारंपरिक काष्ठ कला, तीर कमान व हस्तनिर्मित जैकेट भेंटकर किया। सम्मेलन के दौरान अमित शाह एवं मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को तेंदूपत्ता के लाभांश का वितरण किया। इस दौरान अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 26 जिलों में स्थित 28 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन के निर्णय की प्रक्रिया का शुभारंभ रिमोट के माध्यम से किया। उन्होंने 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम के अधिकार देने की शुरुआत की।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने आदिवासियों को जंगल का मालिक बनाया है। मध्य प्रदेश ने 10 वर्ष में जीडीपी में 200 प्रतिशत की वृद्धि की है। मोदी सरकार आदिवासी समुदाय के ऊपर 78 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि जो 17 निर्णय मप्र सरकार ने आदिवासियों के लिए लिए थे उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में पहली बार किसी सरकार ने आदिवासियों को जंगल का मालिक बनाया है। शिवराज के यह कदम अनुकरणीय हैं।

तेंदूपत्ता की 100 गड्डी पर 300 रुपये मिलेंगे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए 250 रुपये प्रति 100 गड्डी के बजाय 300 रुपये प्रति 100 गड्डी दिए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 जिलों में स्थित 827 से ज्यादा वन ग्रामों के राजस्व ग्राम बनने से जमीनों के खाते बन सकेंगे, व्यवस्थित अभिलेख होगा। इसके साथ ही वन ग्रामों को अन्य ग्रामों की तरह नहीं मिलने वाले लाभ भी अब मिलने लगेंगे।

पेसा एक्ट बदलने की प्रक्रिया शुरू

शिवराज ने कहा कि हमने तय किया था पेसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि आदिवासी भाई-बहनों की जिंदगी बदलने के लिए पेसा एक्ट लागू करने की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो गई है। सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार दिया है। आपने प्रदेश में घने जंगल बढ़ाने का काम किया है। यह जलए जमीन, जंगल आपके हैं। अंग्रेजों ने ऐसे काले कानून बना दिए थे कि घुस नहीं सकते। पत्ता नहीं तोड़ सकते। जिंदगी दूधर कर दी थी। सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार एक क्रांतिकारी कदम है। अब जंगल आप ही बचाएंगे। इसे बदलने की प्रक्रिया भी ग्रामसभा तय करेगी। मध्य प्रदेश ने अपने वनवासी भाइयों को जंगल सौंपने का तय किया है। वन विभाग सिर्फ सहयोग करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज प्रदेश की विभिन्न वनोपज समितियों के प्रतिनिधियों को लाभांश राशि प्रदान कर इन समितियों के सशक्तिकरण का नव मार्ग प्रशस्त किया है। मैं सभी समितियों के प्रतिनिधियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आज 125 करोड़ रुपये 22 लाख तेंदूपत्ता तोड़ने वाले गरीबों के खाते में जाना प्रारंभ होगा, लाभांश आपको होगा। ये अभी तक नहीं होता था, वन ग्राम में रहने वाले किसान भाइयों अब प्राकृतिक आपदा होने पर आपको पर्याप्त मुआवजा देने का अधिकार होगा। अब वन ग्राम राजस्व ग्राम बन जाने से आपके पास जो जमीन है उसके खाते बनेंगे, किस्तबंदी होगी, खसरा-नक्शा आपको प्राप्त होंगे नामांतरण, बंटवारा होगा। जो फैसले हमने जबलपुर में किए थे वे एक-एक करके जमीन पर उतार रहे हैं और गरीबों की जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं।

संगठन पदाधिकारी और मंत्री रहे सभास्थल पर मौजूद

सभास्थल पर केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, फगन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, डॉ एल मुरुगन के अलावा प्रदेश के गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, वन मंत्री विजय शाह, सहकारिता मंत्री अरविन्द भदौरिया, भोपाल के प्रभारी व नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी भाजपा मुरलीधर राव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी मौजूद हैं।



एयरपोर्ट पर प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी किया केन्द्रीय मंत्री का गुलदस्ता भेंटकर स्वागत।

मंच पर तेंदू पत्तों की आकृति से फूल बनाया गया था। जिस पर कार्यक्रम का नाम लिखा गया था।

. एक पत्ती पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का फोटो लगाया गया।

. दूसरे पत्ते पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वन मंत्री विजय शाह की फोटो लगाई गई।

. इसके दोनों ओर स्क्रीन पर कार्यक्रम का प्रसारण किया गया।

. लोगों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर और पंखे लगाए गए। वीआईपी के लिए एसी रूम भी बनाए गए हैं।

. आमंत्रित लोग कार्यक्रम को ठीक से देख और सुन सकें इसके लिए 8 बड़ी और कई छोटी स्क्रीन लगाई गई हैं।

झलकियां....

. भोपाल एयरपोर्ट पर शिवराज सिंह चौहान ने अपने सहयोगियों से भी अमित शाह का परिचय कराया।

. संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने अमित शाह को भगवत गीता देकर स्वागत किया।

. अमित शाह का मुख्य कार्यक्रम जबूरी मैदान पर हुआ।

. जबूरी मैदान पर एक लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है।

. कार्यक्रम के लिए तैयार

लगाया गया था।

.

. दूसरे पत्ते पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वन मंत्री विजय शाह की फोटो लगाई गई।

. इसके दोनों ओर स्क्रीन पर कार्यक्रम का प्रसारण किया गया।

. लोगों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर और पंखे लगाए गए। वीआईपी के लिए एसी रूम भी बनाए गए हैं।

. आमंत्रित लोग कार्यक्रम को ठीक से देख और सुन सकें इसके लिए 8 बड़ी और कई छोटी स्क्रीन लगाई गई हैं।

दुनिया की खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती बना एक कीड़ा, भारत में भी कर रहा फसलों को नुकसान



हलधर किसान। दुनिया की खाद्य सुरक्षा के लिए एक कीड़ा (फॉल आर्मीवॉर्म) चुनौती बनाता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संगठन ने इस कीड़े को लेकर चेतावनी जारी की है। संगठन का कहना है कि यह कीड़ा भारत समेत अब तक 70 देशों में फैल चुका है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संगठन ने कहा है कि यह कीड़ा मक्का और चावल सहित 80 तरह के पौधों पर हमला करता है। एक बार जिस जगह यह पहुंच गया तो वहां की पूरी फसलों को खराब कर देता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, बहुत देर होने से पहले देशों को बचाव और रोकथाम की योजनाएं बनानी होंगी। मुख्य तौर पर अमेरिका में पाए जाने वाले आर्मी वर्म के बारे में कहा जाता है कि ये 2016 में नाइजीरिया पहुंचा। कुछ ही समय में ये अफ्रीका के 44 देशों में फैल गए और अपना पेट भरने के लिए फसलों को अपनी खुराक बनाई।

संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक इस कीट पर लगाम लगाने के लिए करीब 1.2 करोड़ डॉलर खर्च हो चुके हैं। फॉल आर्मीवॉर्म चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना, सब्जी फसलों और कपास सहित 80 से अधिक फसलों पर फीड कर सकता है, लेकिन यह मक्का पसंद करता है।

भारत में ज्वार की खेती को बड़ा नुकसान

फॉल आर्मीवॉर्म कीड़ा 70 फीसदी ज्वार की फसल को अपना निशाना बनाया है और यह सब्जियों तक पहुंच चुका है। भारत में सालाना 20 मीट्रिक टन ज्वार पैदा होता है। इस कीड़े को रोकने के लिए उपाय न किए गए तो यह पूरे उपमहाद्वीप में फैल सकता है।

क्या है फॉल आर्मीवॉर्म कीड़ा

फॉल आर्मीवॉर्म नामक कीड़ा मक्के के पौधों के लिए काफी घातक है। इस कीड़े का प्रमुख भोजन मक्का ही है, यह कीड़ा अपने भोजन की तलाश के लिए एक रात में 1 हजार किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। फॉल आर्मीवॉर्म नामक कीड़ा अपने 4 से 5 दिन के जीवन काल में लगभग 1 हजार अंडा देती है।

बचाव के क्या हैं उपाय

इस कीड़े से मक्के के पौधों को बचाव के लिए प्रमुख दवाई का छिड़काव जरूरी है। वैज्ञानिकों ने बताया कि खेत में छिड़काव सुबह या शाम को ही करना चाहिए दोपहर में छिड़काव करने से दवाई का असर नहीं रहता है।

भारत में ये कीड़े फसलों को पहुंचा रहे नुकसान दीमक: गेहूं, गन्ना, धान व अन्य सभी फल वाले पौधों को नुकसान पहुंचाती है।

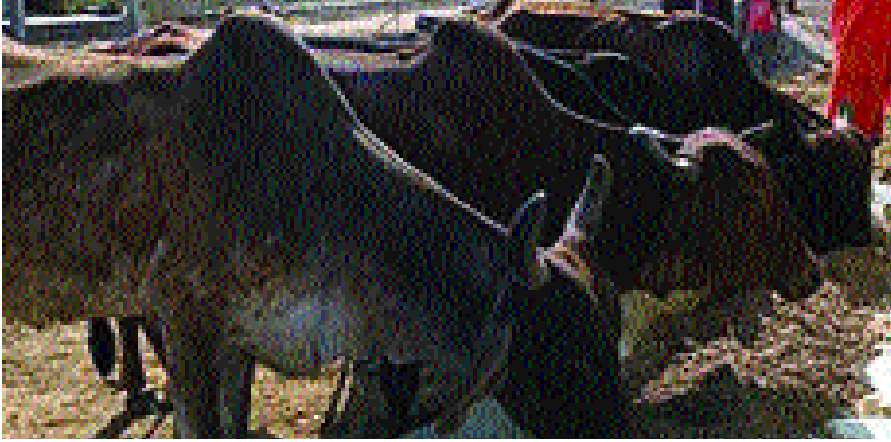
सफेद मक्खी : सब्जियों व चौड़े पत्ते वाले पौधों में ज्यादा नुकसान करती है।

माहू : सरसो, जौ व आलू आदि फसलों के लिए खतरनाक होता है।

टिड्डा : गन्ना, ज्वार, बाजरा आदि को काफी नुकसान पहुंचाता है।

भुआ पिछू : मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली को यह नुकसान पहुंचाती है।

फिर लौटेगा गौ-सदनों का वैभव: स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि, अध्यक्ष गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड



हलधर किसान। मध्यप्रदेश गाओं एवं गौवंश (बछड़े, बछड़ियों, सांड, बैलों) के संरक्षण के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य है। यहां का 951 हजार वर्ग किलोमीटर का जंगल गौवंश का आश्रय स्थल है। सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रकृति और मूक प्राणियों के मध्य एक नैसर्गिक समीकरण बना हुआ है। गाओं का भोजन जंगल में और गोबर एवं गौमूत्र के रूप में जंगल का आहार गाओं के पास। शासन, प्रशासन और आम नागरिकों को मिलकर इस प्राकृतिक समीकरण के आधार पर गौवंश के संरक्षण एवं पालन की दिशा में युगानुकूल सम.सामयिक और नवाचार विधि से कार्य करना चाहिये।

जंगलों में थे 10 गौ.सदन

अविभाजित मध्यप्रदेश के जंगलों में वर्ष 1916 से 10 गौ.सदन होते थे। वर्षा काल में लगभग 3 माह गौपालकों, कृषकों का पालित गौ.वंश जंगलों में बने इन्हीं 10 गौ.सदनों में निवास करता था। दीपावली के आसपास इन गौ.सदनों से कृषकों, गौ.पालकों का गौ.वंश सकुशल घर वापस आ जाता था। प्राचीन भारत का यह किसानों की फसल सुरक्षा एवं गौ.वंश के संरक्षण का पारम्परिक रोडमैप हुआ करता था। ये गौ.सदन वर्ष 2000 तक

व्यवस्थित संचालित होते रहे। गौ.सदनों के पास जंगलों में 7200 एकड़ चरनोई भूमि होती थी। वन विभाग की इस भूमि पर राज्य के पशुपालन विभाग का आधिपत्य रहा।

मध्यप्रदेश का विभाजन होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया और दो गौ.सदन (बिलासपुर और रायपुर के) छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से में चले गये। दुर्भाग्य से मध्यप्रदेश के 8 गौ.सदन अकारण ही भंग कर दिये गये। मध्यप्रदेश में गाओं के समक्ष समस्या तब पैदा हुई जब मध्यप्रदेश के वर्ष 2000 और वर्ष 2003 के कालखण्ड के तत्कालीन शासन ने चरनोई भूमि की बंदरबाँट मनुष्यों में कर दी। जंगलों के गौ.सदन के भंग होने एवं नगरों और ग्रामों की चरनोई भूमि का मनुष्यों में आवंटन ने मूक प्राणियों एवं गौ.वंश आदि के जीवन को संकटग्रस्त कर दिया।

इधर तत्कालीन केंद्र शासन और राज्य शासन की माँस निर्यात नीति एवं कल्लखानों को धड़ल्ले से लाइसेंस जारी करने की नीति ने प्रदेश के गौ.वंशीय तथा अन्य कृषिक पशुधन की महती हानि कर डाली। प्रदेश में विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक सामाजिक एवं अन्यान्य संगठनों के सम्मिलित आन्दोलन, अनुष्ठान अभियान और प्रयासों से प्रदेश में पशुधन रोकने के कड़े कानून बने। आयोगों का गठन हुआ। मध्यप्रदेश गौ.पालन एवं पशुधन

संवर्धन बोर्ड बना।

मालवा क्षेत्र के एक विशाल भू.खण्ड में कामधेनु गौ.अभयारण्य का निर्माण हुआ।

प्रदेश के मध्यभारत, बुंदेलखण्ड, बघेलखण्ड एवं महाकौशल क्षेत्र में भी हमने मालवा क्षेत्र की भाँति अपने प्रयास सम्भावना के आधार पर आरम्भ कर दिये हैं। प्रदेश में शासन की संकल्प शक्ति, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग और सक्रियता से तथा स्वयं सेवी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयत्नों से 627 स्वयं सेवी संगठनों की गौ.शालाएँ और 1265 गौ.शालाएँ मनरेगा के आर्थिक सहयोग से निर्मित ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियाशील हो गई हैं। एक गौ.वंश वन्य विहार रीवा के प्बसावन मामाष् नामक स्थान पर तथा एक गौ.वंश वन्य विहार जबलपुर जिले की कुण्डम तहसील में गंगईवीर जंगल परिक्षेत्र में निर्मित होने जा रहा है। इसी प्रकार जिला सीहोर के देलावाड़ी स्थान पर भी गौ.वंश वन्य विहार निर्माण की प्रक्रिया जारी है। हमें विश्वास है सरकार की नीति, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इच्छा शक्ति तथा मध्यप्रदेश गौ.संवर्धन बोर्ड की तत्परता से प्रदेश में गौ.वंश के संरक्षण एवं संवर्धन का अनुकूल वातावरण निर्मित होकर सकारात्मक और रचनात्मक ठोस परिणाम आगामी एक.दो वर्षों में स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे।

प्राकृतिक खेती के लिए किसान को देसी गाय रखने पर 900 रुपये प्रतिमाह अनुदान देगी मध्य प्रदेश सरकार



भोपाल। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार किसानों को देसी गाय रखने पर प्रतिवर्ष दस हजार 800 रुपये यानी प्रतिमाह नौ सौ रुपये का अनुदान देगी। प्राकृतिक कृषि किट लेने के लिए 75 प्रतिशत तक राशि भी

उपलब्ध कराई जाएगी। खरीफ सीजन से पांच हजार 200 गांवों में प्राकृतिक खेती की गतिविधियां प्रारंभ की जाएंगी। प्रदेशभर में कार्यशालाएँ होंगी और प्रत्येक विकासखंड में पांच पांच पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की सेवाएँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को नीति आयोग द्वारा नवोन्वेषी कृषि पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होकर कही। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन किया है, जो किसानों को प्रोत्साहित करेगा। सभी जिलों में 100.100 गांवों में प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को तैयार किया जाएगा। अगले माह में कृषि से जुड़े विभागों के अधिकारियों के लिए कार्यशाला करेंगे।

उन्होंने बताया कि अब तक एक लाख 65 हजार किसानों ने प्राकृतिक खेती में रुचि दिखाई है। वे स्वयं पांच एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करेंगे। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से भी कहा गया है कि वे भी आगे आएँ ताकि उन्हें देखकर अन्य किसान भी प्रेरित हों। प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय आवश्यक है।

इसके गोबर और मूत्र से ही जीवांमृत तथा धनजीवांमृत बनाए जा सकते हैं। इसके लिए तय किया है कि किसानों को देसी गाय रखने के लिए 900 रुपये प्रति माह यानी 10 हजार 800 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। प्रत्येक गांव में किसान मित्र और किसान दीदी की व्यवस्था भी होगी, जो प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे। इन्हें मानदेय भी दिया जाएगा।

गेहूँ उपार्जन में 24 हजार 762 किसानों को 344 करोड़ का हुआ भुगतान



हलधर किसान। मप्र प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फंज अहमद किदवई ने बताया कि प्रदेश में गेहूँ की बम्पर पैदावार से उपार्जन की प्रक्रिया तीव्र गति से की जा रही है। 24 अप्रैल तक गेहूँ उपार्जन के विरूद्ध 24 हजार 762 किसानों के खाते में 344 करोड़ की राशि अंतरित की जा चुकी है।

अब तक गेहूँ की कुल उपार्जित मात्रा 25 लाख 76 हजार मीट्रिक टन के विरूद्ध 1107 करोड़ रुपये के भुगतान पत्रक तैयार किये जा चुके हैं। साथ ही 23 अप्रैल तक कुल उपार्जित गेहूँ के भुगतान संबंधी सभी कार्यवाही परीक्षण सहित पूरी कर ली

गई हैं। प्रमुख सचिव ने बताया कि गेहूँ उपार्जन के विरूद्ध किसानों को 2 मई 2022 तक सभी लंबित भुगतान पूरे कर दिये जायेंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप 35 हजार किसानों के खाते में लगभग 500 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किये जाने का लक्ष्य है। खाद्य विभाग द्वारा पहली बार किसान को समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान सुनिश्चित करने एवं भुगतान की गई राशि को भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड करने के लिये उपार्जित गेहूँ का भुगतान किसानों के आधार नंबर आधारित बैंक खाते में करने की व्यवस्था की गई है।

उत्पादन में कमी और मांग में भारी बढ़ोतरी के चलते 50 हजार रुपए के स्तर को छू सकता है कपास का भाव

हलधर किसान। इस साल कपास के भावों में बेहिसाब आए उछाल ने पिछले कई सालों का रिकार्ड तोड़ दिया है, जानकार आगे और भाव बढ़ने की उम्मीद जता रहे हैं। ओरिगो ई.मंडी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर (कमोडिटी रिसर्च) तरुण सत्संगी के अनुसार घरेलू वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कॉटन का भाव जल्द ही 50 हजार रुपये के अपने ऊपरी स्तर को छू सकता है। पुरानी फसल आईसीई कॉटन जुलाई वायदा के भाव को 130.25 पर सपोर्ट मिलने के बाद तेजी का रुझान और बन गया है।

बता दें कि कपड़ा और स्पेक्यूलेटिव खरीद की वजह से पुराने फसल के कारोबार में फिलहाल तेजी बनी हुई है। कॉटन का दाम इस बार फिर साढ़े दस साल की ऊंचाई 141.80 सेंट प्रति पाउंड को छूने के बाद इससे पार भी पहुंच सकता है। आने वाले दिनों में कॉटन का दाम 158.173 के ऊपरी स्तर तक पहुंच सकता है। उल्लेखनीय है कि 28 मार्च 2022 को भाव ने साढ़े दस साल की ऊंचाई 141.80 सेंट प्रति पाउंड के स्तर को भी छू लिया था।



देश में कपास की फसल उत्पादन में भारी गिरावट

कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मार्च की रिपोर्ट में 2021.22 सीजन के लिए कपास की फसल के अनुमान में संशोधित करते हुए लगभग कटौती कर दी है। सीएआई ने कपास की फसल के अनुमान को 8 लाख गांठ घटाकर 335.13 लाख गांठ (1 गांठ = 170 किलोग्राम) कर दिया है। सीएआई ने इसके पहले 343.13 लाख गांठ का अनुमान जारी किया था और वही 2021.22 में देश में 353 लाख गांठ कपास

की फसल हुई थी।

अमेरिका में कॉटन फसल पर खतरा
दूसरी ओर नई फसल आईसीई कॉटन दिसंबर वायदा ने भी अपनी रिकार्ड ऊंचाई 120.29 सेंट प्रति पाउंड के स्तर को छू लिया है। उनका कहना है कि वातावरण की गंभीर शुष्क परिस्थितियों की वजह से अमेरिका में टेक्सास में नई फसल के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में कॉटन की कीमतों में आने वाले दिनों में तेजी और बढ़ सकती है।

बीज भण्डार™

भारत में तेजी से बढ़ती हुई रिटेल चैन आउटलेट
सभी कंपनियों के उत्कृष्ट क्वालिटी के बीज मिलने का एक मात्र स्थान
मार्केट मूल्य से कम कीमत पर बीज उपलब्ध



बीज भंडार के **सीड कार्ड** का विमोचन करते हुए माननीय कृषि मंत्री
मध्यप्रदेश शासन श्री कमल जी पटेल एवं खरगोन विधायक श्री रवि जी जोशी



आज ही बीज भंडार में अपनी सदस्यता दर्ज कीजिए और पाइए
आपका स्मार्ट कार्ड – सीड कार्ड।

इतना ही नहीं आपको मिलेंगे सभी कंपनियों
के उच्चतम क्वालिटी के बीज और साथ ही
अर्जित होंगे आपकी हर खरीदी पर अंक।

इसके अलावा कई उत्पादों पर

आकर्षक और विशेष डिस्काउंट



डाउनलोड करें: Google play

अधिक जानकारी के लिए YouTube पर देखें: Beej Bhandar, KisanPlusTv

फॉलो:

**ब्रांच-खरगोन/खंडवा/ कुशी/बडवाह/राजपुर/अंजड/ धामनोद
इंदौर/ जबलपुर/ मंडलेश्वर/ मनावर/ बरगी/ कसरावद**

बीज भंडार की फ्रेंचाइसी लेने के लिए संपर्क करें - 8305103633, 7879428271

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व प्रधान संपादक विवेक जैन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, बलवंत मार्केट, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित व प्रकाशित। Titel Code. MPHIN/2022/37675
, मोबा. नं. 98262 2525, 94254 89337, (समस्य प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)। प्रधान संपादक - विवेक जैन, सलाहकार संपादक - पंकज यादव